taken to absorb them in the said office; and

(c) if so, the reasons for not taking this action for absorption of the staff declared surplus from the office of the Chief Settlement Commissioner, New Delhi, with effect from 1st June, 1972?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Yes, Sir. All the surplus employees from the National Fitness Corps who joined the Central (Surplus Staff) Cell on 1st July, 1972 have already been nominated against vacancies reported by other offices.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पिछड़ क्षेत्रों के विकास के लिए जिला तथा ब्लाक स्तर पर योजना समितियां

3382. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए जिला तथा ब्लाक स्तर पर एक योजना समिति बनाने का प्रस्ताव है और क्या योजना को क्रियान्वित करने के लिये ऐसी विशिष्ट शक्तियां देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । योजना आयोग ने राज्य स्तर पर बहु-स्तरीय आयोजन तथा आयोजन तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है । राज्य सरकारों के साथ मामले पर आगे विचार-विमर्श जारी है ।

अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

3383. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के संबंधित अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग के संबंध में अशोक मेहता समिति की कतिपय सिफारिशें सिद्धांततः मान ली गई हैं तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

ग्रामोद्योग आयोग के लिए सुधार

3384. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी अशोक मेहता समिति ने ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए तथा ग्रामों में फैली बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए "ग्रामोद्योग आयोग" की स्थापना का सुझाव दिया है, यदि हां, तो सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी हां सिफारिश विचाराधीन है ।